



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]
No. 135]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2005/वैशाख 30, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2005/VAISAKHA 30, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 20 मई, 2005

विषय : रूस और चीन जनवादी गणराज्य से 70 मिमी. से 250 मिमी. व्यास वाले कुछेक प्रकार/ग्रेडों के एलॉय तथा गैर-एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स के आयातों से संबंधित मामले में मध्यावधि पाटनरोधी समीक्षा जांच।

सं. 15/6/2004-डीजीएडी.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए रूस, चीन और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कुछेक प्रकार के सीमलेस ग्रेड एलॉय तथा गैर-एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए दिनांक 9 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. 31/1/99 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रूस और चीन जन. गण. (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपशीर्ष 7206.90, 7207.19 और 7207.20 के अंतर्गत आने वाले कुछेक प्रकार के एलॉय तथा गैर-एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउण्ड्स (जिन्हें आगे सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. 31/1/99 के तहत प्रकाशित किए गए थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम 1 जून, 2001 को प्रकाशित किए और सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 25 जून, 2001 को लगाया गया था।

2. मै0 महाराष्ट्र सीमलेस लि0 द्वारा किए गए एक अनुरोध को प्रस्तुत करने के पश्चात्, जिसमें मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता को जरूरी ठहराने संबंधी सकारात्मक साक्ष्य शामिल हैं, प्राधिकारी ने उपरोक्त सम्बद्ध देशों के विरुद्ध लागू शुल्क के संबंध में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमों के नियम 23 के अंतर्गत पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच आरम्भ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 24 मई, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लगातार लगाए रखना अपेक्षित है और क्या शुल्क को समाप्त करने अथवा उसे कम करने, अथवा दोनों ही स्थितियों में क्षति का होना जारी रहेगा अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होगी ।

ख. अपनाई गई प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-
- i) समीक्षा की शुरुआत के पश्चात् प्राधिकारी ने आवश्यक संगत सूचना मंगाने के लिए नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों और भारत में घरेलू उद्योग को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजीं ;
 - ii) नई दिल्ली में सम्बद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को नियम 6(4) के अनुसार समीक्षा जांच-आरंभ करने के बारे में सूचित किया गया था और उनसे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का जवाब देने के लिए उनके संबंधित देशों में निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध किया गया;
 - iii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियाँ भेजी गईं ।
 - iv) यह जांच 1.1.2003 से 31.12.2003 (जांच अवधि) तक की अवधि के लिए की गई थी । यद्यपि क्षति संबंधी जांच एएम 2001, एएम 2002, एएम 2003 और जांच अवधि की अवधि के लिए की गई थी ।

- v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे एकत्र करने का अनुरोध किया गया था।
- vi) एक समीक्षा के लिए मै0 कुणाल कार्पोरेशन, मुम्बई और मै0 फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (एफ आई आई), स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आवेदक के अलावा किसी अन्य निर्यातक, आयातक और संघ से जांच शुरुआत अधिसूचना का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।
- vii) मै0 इंडियन सीमलेस स्टील और एलॉय लि0, पुणे और मै0 कल्याणी स्टील, पुणे ने घरेलू उद्योग की ओर से समीक्षा का विरोध करते हुए अपने उत्तर प्रस्तुत किए।
- viii) प्राधिकारी ने व्यक्त किए गए सभी विचारों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उस सीमा तक विचार किया जहां तक ये मौजूदा जांच के लिए संगत हैं।
- ix) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंशों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा।
- x) प्राधिकारी ने सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के सत्यापन और उनको हुई क्षति की जांच करने और उत्पादन की ईष्टम लागत और भारत में सम्बद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए लागत जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सुनने के लिए 7.12.2004 को एक सार्वजनिक सुनवाई की जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध

किया गया था । प्रत्युत्तरों के साथ हितबद्ध पक्षसकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और अन्य अनुरोधों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में विचार किया गया था । उपरोक्त नियम के नियम 16 के अनुसार इन जांच-परिणामों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधारों को 10 मई 2005 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष रखा गया और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जा रहा है ।

- xii) *** यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माने जाने का द्योतक है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

4. विचाराधीन उत्पाद "कुछेक प्रकार/ग्रेड के एलॉय और गैर-एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउंड्स हैं जिनका व्यास आई एस विनिर्देशन अथवा आई एस मानकों के समान किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्देशन के अनुरूप 70 मिमी. से 250 मिमी. तक है" । दिनांक 9.12.99 की जांच प्रारंभ अधिसूचना (मूल जांच की) और 21.1.2000 के शुद्धिपत्र में यथा-उल्लिखित ग्रेडों की सूची वही रहेगी । याचिकाकर्ता आयातक द्वारा लिखित अनुरोधों में कुछेक विवाद उठाए गए हैं कि संबद्ध वस्तु के कुछेक प्रकारों/ग्रेडों का संगत आई एस वर्गीकरणों में उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें उत्पाद के दायरे से हटाया जाना अपेक्षित है । तथापि उनके दावे के समर्थन में कोई विस्तृत अनुरोध अथवा साक्ष्य प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रकटन विवरण जारी करने के पश्चात् याचिकाकर्ता आयातक ने पुनः यह दोहराया है कि सभी 29 ग्रेड उत्पाद कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं आते हैं और कुछ आई.एस. विनिर्दिष्टताएं बी.आई.एस. विनिर्दिष्टता सूची से हटा दी गई है और इसलिए सभी 29 ग्रेड विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र के भीतर जारी नहीं रखे जा सकते हैं । प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता आयातक के तर्क की जांच की है और यह नोट करते हैं कि उनके तर्क सुस्थापित हैं और किसी साक्ष्य से बाधित नहीं होते हैं । उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की पुष्टि करते हैं जैसाकि मूल जांच और समीक्षा की शुरुआत (शुद्धिपत्र को साथ पढ़ें) में भी निर्णय लिया गया और माना गया है । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची 1 के उपशीर्ष 7206.90, 7207.19 और 7207.20 के अंतर्गत वर्गीकृत

है । यद्यपि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है ।

घ. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दे और प्राधिकारी द्वारा जांच

घ.1 स्थिति, घरेलू उद्योग और संबंधित पक्षकारों के मुद्दे - घरेलू उद्योग, याचिकाकर्ता के विचार और प्राधिकारी द्वारा जांच

5. समीक्षा के लिए याचिकाकर्ता मै0 महाराष्ट्र सीमलेस लि0 (एम एस एल) ने पने लिखित अनुरोध में एक प्रत्युत्तर के बाद दावा किया है कि मै0 कल्याणी स्टील्स लिमि0 (के एस एल) और मै0 इंडियन सीमलेस स्टील एलॉयज लि0 (आई एस एस ए एल) दोनों को आयातक के साथ उनके संबंध के कारण घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता । अपने तर्क में याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि मै0 आई एस एस ए एल मै0 इंडियन सीमलेस मेटल ट्यूब्स लि0 (आई एस एम टी) को संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है और 1 अप्रैल 2003 से दोनों कंपनियाँ संयुक्त पुनर्गठन प्रस्ताव कर रही हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ दोनों कंपनियों के विलय का प्रावधान है । उन्होंने दावा किया है कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत यह विश्वास करने के आधार मौजूद हैं कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है कि जिसके कारण दोनों कंपनियां गैर-संबद्ध कंपनियों से अलग व्यवहार कर रही हैं, जैसा कि नियम 2 (ख) से स्पष्टीकरण (क) के अंतर्गत अपेक्षित है और इसलिए आई एस एस ए एल और आई एस एम टी दोनों को एक दूसरे से संबंधित माना जाना चाहिए । इसी प्रकार याचिकाकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि इस तथ्य के आधार पर कि मै0 के एस एल का आई एस एम टी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके एक निदेशक दोनों कंपनियों में कार्यरत हैं, इन दोनों कंपनियों को एक दूसरे से सम्बद्ध माना जाना चाहिए । उपरोक्त के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि मै0 के एस एल और मै0 आई एस एस ए एल दोनों आई एस एम टी से संबंधित हैं, जोकि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु का आयातक है और इसलिए नियम 2 (ख) के अनुसार उन्हें घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता ।
6. याचिकाकर्ता ने आगे घरेलू उद्योग के दावे पर विवाद किया है कि मै0 के एस एल, आई एस एस ए एल और जे एस पी एल का भार में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का 100% बनता है । उन्होंने दावा किया है कि कुल घरेलू उत्पादन में

अन्य घरेलू उत्पादक जैसे म्यूस्को और सेल, दुर्गापुर को उनके घरेलू उद्योग में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया है कि वे पाटनरोधी नियमों के अर्थों के भीतर मै0 जे एस पी एल से सम्बद्ध नहीं हैं। अतः उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि जे एस पी एल को एक घरेलू उत्पादक के रूप में माना जाए जिसने याचिका का विरोध किया है और अतः प्राधिकारी से के एस एल और आई एस एस ए एल की स्थिति की जांच संगत पाटनरोधी नियमों के अनुसार करने का अनुरोध किया है।

7. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता और घरेलू उद्योग के दावे की जांच की है। गौण स्रोतों से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि सम्बद्ध देशों से जांच अवधि के दौरान आई एस एम टी द्वारा सम्बद्ध वस्तु की 412 मी.टन की छोटी मात्रा आयात की गई थी। तथापि इस मात्रा को अपर्याप्त माना गया है क्योंकि यह जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा आयातित सम्बद्ध वस्तु के 2% से कम बनती है और जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की कुल मांग के 1% से कम है। तदनुसार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आई एस एम टी द्वारा जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु की बहुत कम मात्रा का आयात किया गया है और इसलिए मै0 के एस एल और आई एस एस ए एल के आयातक (आई एस एम टी) के साथ संबंधों के बारे में तर्कों का कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता आयातक द्वारा प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यह मानने के लिए कोई आधार है कि घरेलू उद्योग और आयातक के बीच संबंध का प्रभाव ऐसा है कि जिसके कारण दोनों कंपनियां गैर-संबद्ध कंपनियों से अलग व्यवहार कर रही हैं। उपरोक्त के मद्देनजर मै0 के एस एल और मै0 आई एस एस ए एल दोनों को पाटनरोधी नियमों के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग माना जा रहा है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता आयातक के तर्क की जांच की है और पुनः यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के प्रपत्र के अनुसार अपनी बिक्री कीमतों और उत्पादन लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए मै0 जेएसपीएल को पर्याप्त अवसर दिया गया था। तथापि, उन्होंने संबद्ध जांच में हिस्सा लेना पसंद नहीं किया और इसलिए प्राधिकारी ने इस प्रकटन विवरण के अनुबंध III में यथा उल्लिखित क्षति के प्रयोजनार्थ मै0 के एस एल और मै0 आई एस एस ए एल की जांच की है।

घ.2 अन्य मुद्दे: समीक्षा की शुरुआत: याचिकाकर्ता आयातक, घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क और प्राधिकारी द्वारा जांच

8. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित एडीए वे अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत समीक्षा के आधारों को

सही साबित करना अनिवार्य है और आवेदक ऐसा करने में विफल रहा है । इसलिए समीक्षा की शुरुआत त्रुटिपूर्ण है । आवेदक आयातक ने यह तर्क दिया है कि भारतीय कानून में प्राधिकारी से समय समय पर शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने की अपेक्षा की गई है और इसमें समीक्षा की जांच करने वाले पक्षकार पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने का दायित्व नहीं है । तथापि, जैसाकि एडीए के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत अपेक्षित है, उन्होंने अनेक आधारों संबंधी सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराई थी और प्राधिकारी के पास समीक्षा की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध थी । घरेलू उद्योग ने आगे यह दावा किया है कि शुल्क हटाने की आवश्यकता सिद्ध करने का दायित्व याचिकाकर्ता का है, क्योंकि समीक्षा जांच शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए की जाती है । चूंकि याचिकाकर्ता शुल्क वापस लेने की आवश्यकता को सिद्ध करने में विफल रहा है इसलिए प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाना चाहिए ।

9. प्राधिकारी ने इस समीक्षा जांच की शुरुआत के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की है ।
10. करार के अनुच्छेद 11.2 में यह व्यवस्था है कि प्राधिकारी अपनी ओर से अथवा किसी हितबद्ध पार्टी जो समीक्षा करने की जरूरत का समर्थन करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर जहां आवश्यक हो शुल्क के लगाए रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात एक उचित समयावधि समाप्त हो गई हो । हितबद्ध पार्टियों के पास प्राधिकारियों से इस बात की जांच हेतु अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को निरंतर लगाए रखना आवश्यक है अथवा यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है अथवा इसमें परिवर्तन किया जाता है अथवा दोनों स्थितियों में क्या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी । इस पैराग्राफ के अन्तर्गत समीक्षा के परिणामस्वरूप यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है तो, इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा । प्राधिकारी ने इन तर्कों की जांच की है और उनका यह विचार है कि समीक्षा की शुरुआत करने के लिए प्राधिकारी के पास ऐसी सकारात्मक सूचना होनी चाहिए जिस पर वह ये निर्णय लेने के लिए विश्वास कर सकें कि क्या शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए समीक्षा अपेक्षित है । इस मामले में आवेदक ने अपने समीक्षा संबंधी आवेदन में प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की थी और प्रस्तुत की गई सकारात्मक सूचना के आधार पर समीक्षा की शुरुआत की गई थी । साक्ष्यों को प्रस्तुत करने

से दावे सही साबित होते हैं और विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए विरोधी दावे जांच का विषय हैं तथा इन्हें जांच प्रक्रिया के दौरान समीक्षा के लिए अनुरोध करने वाले पक्षकार समेत सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। तथापि समीक्षा का परिणाम इस समीक्षा में विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

घ.3 अन्य मुद्दे: स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य आयातकों द्वारा उठाये गये मुद्दे

11. स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह अनुरोध किया है कि देश भर की इस्पात री-रोलिंग मिलों के लिए बिलेट्स प्रमुख कच्ची सामग्री है जो देश में तैयार इस्पात की मांग के 58% हिस्से को पूरा करती है और बड़ी संख्या में निचले स्तर के उद्योग इस्पात री-रोलर्स के उत्पादन पर निर्भर हैं। उन्होंने स्टील री-रोलर्स और निचले स्तर के उद्योगों के लिए बिलेट्स की उपलब्धता बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि सभी प्रकार के इस्पातों पर और सभी देशों से पाटनरोधी शुल्क को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए क्योंकि पाटन शुल्क स्टील की वैश्विक कीमतों के अधिन्य के समय स्थानीय स्टील उद्योगों को संरक्षित करने के लिए लागू किये गये थे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

12. प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में क्षति से संबंधित निष्कर्षों के पैरा में लिए गए अपने विश्लेषण में दावे की जांच की है।

ड. पाटन का निर्धारण

13. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य रूप से तुलनीय मूल्य जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र से उपयोग के निमित्त हो जिसका निर्धारण उप-धारा (6) के अंतर्गत नियमों के अनुसार किया गया हो; या

जब व्यापार के सामान्य रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री न हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा:

समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उपयुक्त तीसरे देश से किया जाए जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो; या

उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपयुक्त राशि जोड़ी गई हो जिसका निर्धारण उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो ;

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से इतर किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु को निर्यात वाले देश से होकर केवल वाहनान्तरित किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता हो या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं हो तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

14. प्राधिकारी ने धारा 9 (क)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं । किसी भी निर्यातक ने किसी भी रूप में जांच शुरूआत तथा प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और परिणामस्वरूप उन्हें इस जांच में असहयोगी माना गया है ।
15. किसी भी ज्ञात निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली में उल्लिखित विभिन्न परिशिष्टों के संबंध में सूचना देकर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ।

(क) सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत:

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के अंतर्गत यथापेक्षित ढंग से कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने गैर बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के 8(3) में यथा उल्लिखित परिकल्पनाओं का खंडन करते हुए भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । चूंकि विभिन्न परिशिष्टों के अंतर्गत कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है; इसलिए प्राधिकारी ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि क्या घरेलू बिक्रियाँ व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से की गई हैं । निर्यातक से संगत सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और रूस के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण प्रयोज्य समायोजनों के साथ रूस से हुए आयातों की कुल

मात्रा को ध्यान में रखते हुए भारत को भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है। चूंकि चीन जन.गण. से आयातों के मामले में कोई निर्यात कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस समीक्षा में किसी पाटन मार्जिन के निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव नहीं है। प्रकटन विवरण जारी करने के पश्चात आयातक याचिकाकर्ता ने विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से सामान्य मूल्य के घटकों और वे आधार प्रकट करने का अनुरोध किया है जिन पर ये घटक तैयार किए गए हैं। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता आयातक के तर्क की जांच की है और नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ तैयार की गई सामान्य कीमत चीन जनवादी गणराज्य और रूस से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटनरोधी नियामावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार परिकलित की गई है और सामान्य मूल्य परिकलित करते समय भारत में उत्पादन लागत को उचित लाभ के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को शामिल करते हुए विधिवत समायोजित किया गया है। क्योंकि कुछ सूचना घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से संबंधित है, इसलिए सामान्य मूल्य से संबंधित विवरण प्रकट नहीं किया गया है।

(ख) तुलना

17. कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने के प्रयोजनार्थ उन अंतरों के लिए समायोजनों के रूप में अपेक्षित छूट दी गई थी जिनसे कीमतों और कीमत तुलनीयता पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) पाटन मार्जिन:

18. पाटनरोधी नियामावली के अनुबंध 1 के नियम 6(iv) के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण भारित औसत निर्यात कीमत के साथ भारित औसत सामान्य मूल्यों के आधार पर किया गया था। इस तुलना में जांच अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन की मौजूदगी प्रदर्शित हुई थी। निर्यात कीमत के प्रतिशत रूप में व्यक्त भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और रूस के लिए ये 36.56% है। चूंकि जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से कोई निर्यात किये गये हैं, इसलिए समीक्षा जांच के दौरान कोई नये पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किये गये हैं पूरी जांच के दौरान यथा निर्धारित पाटन मार्जिन(105%) पर इस समीक्षा जांच में विचार किया गया है।

	सामान्य मूल्य अम.डा./मी.टन	निर्यात कीमत अम.डा./मी.टन	पाटन मार्जिन अम.डा./मी.टन	पाटन मार्जिन %
रूस	****	****	****	36.56

च. क्षति का निर्धारण

च.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

19. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(iii) में यह अपेक्षा की गई है कि जिस मामले में किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देशों से हुआ है और उनकी एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही हो, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन तब करेंगे, जब यह निर्धारित होता हो कि:
 - i) प्रत्येक देश से आयात या तो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हो या समग्र रूप से आयातों के 7% से अधिक हों;
 - ii) प्रत्येक देश के विरुद्ध पाटन मार्जिन 2% से अधिक हो; और
 - iii) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं के आलोक में उचित हो।
20. इस संबंध में प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयात आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह पाया है कि जाँच अवधि के दौरान और इससे तीन वर्ष पहले से चीन जन.गण. से कोई आयात नहीं हुए हैं। चूंकि इस देश में चीन जन.गण. से कोई आयात नहीं हुए हैं, इसलिए प्राधिकारी ने एडीए के अनुच्छेद 3.4 में यथा उल्लिखित और पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार विभिन्न मापदंडों के संबंध में केवल रूस से पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

च.2 क्षति का जारी रहना

च.2.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार और प्राधिकारी द्वारा जाँच

21. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि रूस के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में सामग्री का पाटन जारी रखा था। निर्यात कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि का द्योतक है। तथापि उत्पादन लागत में पूरी वृद्धि पर भी निर्यातकों द्वारा पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है और पाटन मार्जिन में वस्तुतः वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण चीन के निर्यातक सामग्री का निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में पाटन पुनः शुरू हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की आशंका है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति उठानी पड़ रही है, फिर भी इसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा,

यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती हो रही है।

22. जहां तक घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग का संबंध है, घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री में वृद्धि पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप हुई है, जिसके द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में होने वाली गिरावट को रोका जा सका और घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में सुधार करने हेतु सहायता प्राप्त हुई। तथापि, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया गया, तो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से आयात अत्यधिक सस्ते हो जाने के कारण बिक्री मात्रा एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पादन एवं क्षमता उपयोग को क्षति पहुंचने की संभावना है। जहां तक घरेलू उद्योग की उत्पादकता का संबंध है, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने एवं उत्पादन में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उसमें सुधार आया है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग की उत्पादकता कम हो जाने की संभावना है।

23. लाभ/हानि, नकद प्रवाह तथा लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क है कि पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने से इन मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, चूंकि ओईएमके पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था इसलिए घरेलू उद्योग उचित लाभ तो क्या, सामान्य लाभ प्राप्त करने में भी असमर्थ रहा है।

24. घरेलू उद्योग द्वारा यह निवेदन किया गया था कि विचाराधीन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। यद्यपि उद्योग उचित लाभ अर्जित नहीं कर रहा था तथापि इस अवधि के दौरान लाभप्रदता में सुधार आया है। तथापि वर्तमान शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों का सस्ता हो जाना स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों में उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग या तो अपनी कीमतें कम करे (जिसका अर्थ लाभ, नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय में कमी होना है) अथवा बिक्री में हानि उठाए। दोनों ही स्थितियों में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की संभावना है। इसके अलावा, पाटित आयातों के बाजार हिस्से के स्तर को देखते हुए, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के हटा लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आने की संभावना है।

25. आगे यह निवेदन किया गया है कि रूस एवं यूक्रेन से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती हो रही है। यद्यपि सीआईएफ कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत एवं उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि वर्तमान जांच, समीक्षा जांच है तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच समीक्षा के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी हद तक कटौती हो रही है। यदि वर्तमान शुल्क हटा लिए जाते हैं तो कीमत कटौती की सीमा और अधिक बढ़ जाएगी जिससे आगे और अधिक आयात होने की अत्यधिक संभावना है। अन्य कारकों के साथ-साथ घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता, वर्तमान उपायों के साथ किए जा रहे आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती, निर्यातकों की पर्याप्त उत्पादन क्षमता, आयातों का उल्लेखनीय बाजार हिस्सा, निर्यातकों की बाजार स्थिति एवं परिस्थिति, विदेशी उत्पादकों की निर्यात संबंधी स्थिति, भारतीय बाजार की आकर्षक कीमतें जैसे कारक उद्धृत किए हैं।
26. जहां तक पाटित कीमतों पर आयात की मात्रा एवं मूल्य की बिक्री न होने का संबंध है, यह कहा गया है कि पाटित आयातों के अलावा अन्य कोई आयात मौजूद नहीं है अर्थात् गैर-पाटित आयातों की मात्रा एवं मूल्य न्यूनतम सीमा के भीतर है। इसके अलावा विचाराधीन उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। जहां तक खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन का संबंध है, यह भी कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं है जिसके द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती हो और उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्पादकता, जिसे प्रति व्यक्ति उत्पादन के संदर्भ में मापा जाता है, में वृद्धि हुई है। अतः घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क समाप्त न किए जाएं।
27. याचिकाकर्ता मै0 महाराष्ट्र सीमलेस लि0 (एम एस एल) तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों ने अपने विभिन्न निवेदनों में यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है तथा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। संक्षिप्तता के ख्याल से हितबद्ध पार्टियों द्वारा उनके विभिन्न लिखित निवेदनों में

दिए गए विभिन्न तर्कों को इस जांच में दोहराया नहीं गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि आयात वर्ष 2000 में 39830 मी.टन की तुलना में घटकर वर्ष 2003 में 27857 मी.टन के हो गए हैं। उसी अवधि में सी आई एफ कीमत 10390 रूपए प्रति मी.टन से बढ़कर 14702 प्रति मी.टन हो गई है। वर्ष 2004 में आयात मात्रा बढ़कर 41802 प्रति मी.टन और कीमतें बढ़कर 19634 प्रति मी.टन हो गई। जहां पिछले 5 वर्षों में मात्रा में लगभग 5% की वृद्धि हुई वहीं कीमतों में 89% से अधिक की वृद्धि हुई। इसके अलावा, जहां कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई जो कायम रही। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कीमतों का मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्रा पर कीमतों का प्रभाव यद्यपि पूरी तरह शून्य तो नहीं है वरन बहुत मामूली है। आयात मात्रा पर आयात कीमतों के प्रभाव की जांच करते समय भारत में प्रचलित कीमतों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। एम.एस.एल. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि जुलाई 2003 से अप्रैल 2004 तक प्रत्येक महीने में आयात कीमतें भारतीय घरेलू उद्योग की औसत बिक्री से अधिक है। इससे यह भी साबित होता है कि आयात मात्रा में वृद्धि कीमतों के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई है। यदि मात्रा पर कीमतों का प्रभाव पड़ता तो -

- i) आयात कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि; और/अथवा
- ii) घरेलू कीमतों के आयात कीमतों से कम होने की स्थिति में, आयात मात्रा में गिरावट आनी चाहिए थी।

क. दोनों ही स्थितियों में आयात मात्रा में गिरावट नहीं आई। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग, आयात कीमतों की तुलना में काफी कम कीमत पर बिक्री कर रहा था इसलिए आयात की वस्तुओं द्वारा किसी प्रकार की कीमत कटौती नहीं हुई है।

ख. अतः घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता है कि उन्हें आयातित वस्तुओं द्वारा क्षति पहुंची है। कीमत कटौती के अभाव में कारणात्मक संबंध का भी स्पष्टतः अभाव रहेगा।

28. वर्ष 1999-2000 के दौरान एम एस एल ने अपनी 70% आवश्यकताओं को आयात द्वारा तथा 30% आवश्यकताओं को भारतीय घरेलू उद्योग से खरीद के

माध्यम से पूरा किया। वर्ष दर वर्ष, परिस्थिति में बदलाव आया तथा वर्ष 2002-03 में आयात केवल 6% रह गए क्योंकि एम एस एल अपनी आवश्यकताओं का 94% से अधिक हिस्सा भारतीय घरेलू उद्योग से क्रय कर रहा था। फिर भी, आयातों में कुछ वृद्धि हुई थी। ऐसा प्रमुखतः भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा एम एस एल के आवश्यक मात्रा की आपूर्ति न कर पाने के कारण हुआ था। इधर कुछ समय से भारतीय घरेलू उद्योग अपनी व्यापार वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि अब भारतीय घरेलू उद्योग संबद्ध उत्पाद जो कि अर्द्ध-परिष्कृत इस्पात की बजाय मूल्यवर्धित उत्पाद पर अधिक ध्यान दे रहा है। घरेलू उद्योग को अपनी उत्पाद संबंधी प्राथमिकता तय करने का पूरा अधिकार है परंतु जब यह प्राथमिकता उसके प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के आड़े आती है तो प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के अन्य स्रोतों का पता लगाने के लिए विवश होना पड़ता है। यही कारण है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जा रही वस्तु की तुलना में महंगी होने के बावजूद आयात में वृद्धि हो रही है। अतः आयात में वृद्धि मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण हो रही है, कीमत के कारण नहीं - चाहे वह आयात कीमत हो अथवा घरेलू वस्तु की कीमत।

29. मूल जांच के समय, स्टील उद्योग विश्व भर में मंदी का सामना कर रहा था। वैश्विक रूप से, इस्पात की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आने के कारण इस्पात कंपनियां अत्यधिक दबाव में थी। पिछले 5 वर्षों में, परिस्थिति में काफी बदलाव आया है। इस्पात की कीमतों में अपेक्षा से अधिक सुधार हुआ है। इस्पात उद्योग काफी उच्च लाभ का अर्जन कर रहा है।
30. जे एस पी एल तथा कल्याणी स्टील के तुलन पत्र में अवलोकन से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की दोनों इकाइयों ने अपने वार्षिक लेखों में कर पश्चात लाभ प्रदर्शित किया है। जिंदल तथा कल्याणी दोनों के लिए वर्ष 2002-03 में लाभ में क्रमशः 35% और 51% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 में भी दोनों कंपनियों के लिए लाभों में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार के बड़े लाभों से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग बहुत अच्छी स्थिति में है।
31. आयातक ने कल्याणी के साथ ई-मेल द्वारा हुए विचारों के आदान-प्रदान संबंधी प्रतियां संलग्न की हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने वस्तु की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करने और अपनी वचनबद्धता को पूरा करने से इंकार किया

है। दी गई दृढ़ वचनबद्धता के बावजूद कल्याणी द्वारा आपूर्ति नहीं की जा रही है। कल्याणी से आपूर्ति की अपेक्षित मात्रा प्राप्त न होने के कारण, एम एस एल के पास आवश्यकता से अधिक कीमत का भुगतान करके संबद्ध वस्तु का आयात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह भी कहा गया है कि एम एस एल द्वारा किए गए आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग से खरीदी गई सामग्री की कीमत से लगातार उच्च रहा है। यह "उत्क्रमण कारणात्मक संबंध" का एक अनोखा उदाहरण है अर्थात् भारतीय प्रयोक्ता को घरेलू उद्योग द्वारा बेची जा रही वस्तु की कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर वस्तु का आयात करने हेतु विवश होना पड़ता है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित मात्रा में वस्तु की आपूर्ति नहीं की जाती है।

ड.2.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. भारतीय नियमावली तथा डब्ल्यू टी ओ करार में समीक्षा जांच करने के मानदंडों का प्रावधान किया गया है। मध्यावधि समीक्षा का मूल उद्देश्य, पाटनरोधी शुल्क के निरंतर लगाए जाने का औचित्य न होने पर, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करना है। एडीए के अनुच्छेद 11.1 से 11.3 में इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

11.1 पाटनरोधी शुल्क केवल उतने समय तक उतनी सीमा तक लागू रहेगा जो क्षतिकारी पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो।

11.2 प्राधिकारी अपनी ओर से अथवा किसी हितबद्ध पार्टी जो समीक्षा करने की जरूरत का समर्थन करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर जहां आवश्यक हो शुल्क के लगाए रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात एक उचित समयावधि समाप्त हो गई हो। हितबद्ध पार्टियों के पास प्राधिकारियों से इस बात की जांच हेतु अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को निरंतर लगाए रखना आवश्यक है अथवा यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है अथवा इसमें परिवर्तन किया जाता है अथवा दोनों स्थितियों में क्या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। इस पैराग्राफ के अन्तर्गत समीक्षा के परिणामस्वरूप यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते

हैं कि पाटनरोधी शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है तो, इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा ।

33. समीक्षा जांच शुरू करने के संबंध में, नियम में निम्नानुसार प्रावधान है:

- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के सतत लागू रहने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और यदि प्राप्त सूचना के आधार पर वे इस बात से संतुष्ट होते हैं कि ऐसे शुल्क के लागू रहने का कोई औचित्य नहीं है तो केन्द्र सरकार को इसे हटाने की सिफारिश करेंगे ।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई समीक्षा को ऐसी समीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीनों की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा ।
- (3) समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

34. उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य न होने पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा । इसके अलावा नियम 11 के अनुसार किसी समीक्षा में घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच "आवश्यक परिवर्तनों सहित" की जानी है । अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य है अर्थात् क्या घरेलू उद्योग को अब कोई क्षति नहीं हो रही है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

35. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों में उनके द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने के मुद्दे की जाँच प्राधिकारी के समक्ष दिए गए इन तर्कों के आलोक में की गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूँकि समीक्षा की शुरुआत पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार की गई है जिसमें प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जाँच किया जाना अपेक्षित है, इसलिए प्राधिकारी ने मामले के पाटन एवं क्षति के पहलुओं के बारे में जाँच के दौरान

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों को ध्यान में रखते हुए पाटन एवं क्षति की मात्रा एवं प्रभाव और शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जाँच करने के लिए यह समीक्षा की है ।

36. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ में (क) पाटित आयातों की मात्रा एवं समान उत्पाद की घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का अनुवर्ती प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जाँच का प्रावधान है । प्राधिकारी द्वारा यह जाँच की जानी अपेक्षित होती है कि क्या आयातों में समग्र रूप से अथवा आयातक सदस्य के उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह जाँच की जानी अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा भारी ह्रास होगा या कीमत में होने वाली ऐसी वृद्धि अवरुद्ध होगी जिसमें अन्यथा काफी बढ़ोतरी हो गई होती ।
37. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने क्षति की मौजूदगी और पाटन एवं क्षति की बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की जाँच करने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत संबंधी प्रभाव तथा कीमतों एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जाँच की है ।
38. चूँकि संबद्ध देशों से निर्यातों के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है इसलिए क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंध की जाँच के प्रयोजनार्थ उन देशों से समग्र निर्यातों को पाटित आयात माना गया है । इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी के समक्ष इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि आयातित संबद्ध वस्तुएँ गैर अलॉय स्टील बिलेट्स, राउण्ड्स तथा बार्स हैं और वे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं बेची जा रही गैर अलॉय बिलेट्स राउण्ड्स एवं बार्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं । इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया है कि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत में बहुत अधिक भिन्नता है और संबद्ध वस्तु की गैर अलॉय ग्रेडों की कीमतें संबद्ध वस्तु की अलॉय ग्रेड की कीमतों से बहुत कम हैं । अतः कीमत कटौती मार्जिन के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु (सभी गैर अलॉय ग्रेड की हैं) के पहुँच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग (गैर अलॉय ग्रेड) की निवल

बिक्री प्राप्ति से की है। तथापि, घरेलू उद्योग के सभी अन्य कीमत प्रभावों के लिए घरेलू समान उत्पाद (सभी ग्रेडों वाले) की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति पर विचार किया गया है। प्रकटन विवरण जारी करने के पश्चात याचिकाकर्ता आयातक ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के सभी प्रभावों की नान-एलाय आयात कीमतों के साथ तुलना करनी चाहिए। उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि उत्पादन लागत का मूल्यांकन और एलाय तथा नॉन-एलाय उत्पादों की अलग-अलग निवल बिक्री वसूलियों द्वारा क्षति का निर्धारण किया जाए। घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण के उत्तर में प्राधिकारी से उनके द्वारा यथानिर्धारित भारित औसत आधार की तुलना में मासिक आधार पर कीमत प्रभाव की जांच करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने दोनों हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की जांच की है और वे यह नोट करते हैं कि कीमत कटौती मार्जिन के लिए जांच अवधि के लिए घरेलू आयात कीमतों (जिनमें सभी नान-एलाय हैं) के साथ घरेलू उद्योग की नान-एलाय संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमतों की जांच की है। यह भी नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित आंकड़े पृथक् रूप से उपलब्ध नहीं थे और इसलिए प्राधिकारी घरेलू समान उत्पाद पर कुल मिलाकर अन्य कीमत प्रभावों का मूल्यांकन किया है।

मात्रा प्रभाव और कीमत प्रभाव: समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और पाटित आयातों का प्रभाव

आयात की मात्रा तथा संबद्ध देशों का हिस्सा और कुल माँग

39. घरेलू उद्योग तथा याचिकाकर्ता (आयातक) ने अनुरोध किया था कि इस तथ्य के कारण कि डीजीसीआई एंड एस आँकड़े उत्पाद के पूर्ण विवरण को नहीं दर्शाते हैं और यह उत्पाद आईटीसीएचएस वर्गीकरण के छह या आठ अंकीय स्तर में अनन्य रूप से वर्गीकृत नहीं है, डीजीसीआई एंड एस के सौदे-वार आँकड़ों में से संबद्ध वस्तु को अलग करना कठिन है। अतः, उन्होंने संबंधित अवधि के लिए आईबीआईएस तथा इम्पेक्स सांख्यिकी जैसे गौण स्रोतों में प्रकाशित आयात आँकड़ों पर भरोसा किया है।

मात्रा मी.टन में

घरेलू खपत/माँग				
	2000-01	2001-02	2002-03	जन.- दिस. '03
संबद्ध देश	31,095	18,384	3,460	27,312
गैर संबद्ध देश	-	-	-	1,496
कुल आयात	31,095	18,384	3,460	28,808
घरेलू उद्योग	166695	176644	184977	165343
अन्य उत्पादक	59687	75274	110313	109216
घरेलू माँग	257,477	270,302	298,750	303,367

40. उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू माँग में 17% वृद्धि हुई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में 5.2% गिरावट आई है। जाँच अवधि के दौरान और जाँच अवधि से पूर्व के तीन वर्षों के दौरान दो संबद्ध देशों में से एक चीन जन.गण. से आयात नगण्य रहे हैं।

कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा					
वास्तविक आंकड़े एवं आयातों में बाजार हिस्सा					
		2000-01	2001-02	2002-03	जन.-दिस.'03
चीन (मात्रा)		-	0	0	0
बाजार हिस्सा				0.00	0.00
रूस (मात्रा)		31095	18,384	3460	27312
बाजार हिस्सा		100.00	100.00	100.00	94.80
	परिवर्तन %		-	-	(5.20)
कुल आयात (संबद्ध देश)		31,095	18,384	3,460	27,312
कुल बाजार हिस्सा		100.00	100.00	100.00	94.80
	आधार वर्ष की तुलना में परिवर्तन		-	-	(5.20)
अन्य देश		-	0	0	1497
कुल आयात		31,095	18384	3460	28809
अन्य बाजार हिस्सा		0.00	0.00	0.00	5.20

आयात कीमतों में वृद्धि

पाटित आयातों की औसत कीमत (सीआईएफ) एवं घरेलू उद्योग की घरेलू कीमत				
	2000-01	2001-02	2002-03	जन.-दिस.'03
सूचीबद्ध (आयात कीमत)	100.0	102.1	102.6	139.8
घरेलू कीमतें (सूचीबद्ध)	100.0	94.8	101.9	115.9

41. उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों की सीआईएफ कीमतों में 39% से अधिक वृद्धि हुई है जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू कीमतों में 15% से अधिक वृद्धि हुई है।

संबद्ध तथा अन्य देशों से कीमत कटौती (पीयूसी)	
वास्तविक आँकड़े	
	जन. - दिस., 03 (रु./मी.टन)
पहुँच कीमत (अन्य)	16436.29
बिक्री कीमत (गैर अलॉय ग्रेड)	*****
कीमत कटौती तथा अन्य से कीमत कटौती %	***** (10-20%)
संबद्ध देशों से पहुँच कीमत	18883
बिक्री कीमत (गैर अलॉय ग्रेड)	*****
गैर अलॉय स्टील के लिए कीमत कटौती	*****
कीमत कटौती प्रतिशत	1-2%

42. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी के समक्ष इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि आयातित संबद्ध वस्तुएँ गैर अलॉय स्टील बिलेट्स, राउण्ड्स तथा बार्स हैं और वे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं बेची जा रही गैर अलॉय बिलेट्स राउण्ड्स एवं बार्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया है कि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत में बहुत अधिक भिन्नता है और संबद्ध वस्तु की गैर अलॉय ग्रेडों की कीमतें संबद्ध वस्तु की अलॉय ग्रेड की कीमतों से बहुत कम हैं। अतः कीमत कटौती मार्जिन के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु (सभी गैर अलॉय ग्रेड की हैं) के पहुँच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग (गैर अलॉय ग्रेड) की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। यद्यपि कीमत कटौती सकारात्मक है तथापि उसे

अत्यधिक (2% से कम) नहीं माना गया है। यहाँ संबद्ध वस्तु के पहुँच मूल्य का निर्धारण वर्तमान पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना किया गया है।

कीमत ह्रास

पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
बिक्री कीमत	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	100.00	95	102	117

43. जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के घरेलू समान उत्पादों का कोई कीमत ह्रास नहीं हुआ है।

कीमत अवमूल्यन

रू./मी.टन	एएम01	एएम02	एएम03	जाँच अवधि
पहुँच मूल्य-पाटित आयात	14591	14901	14971	18883
सूचकांक	100	102.125	102.604	129.42
निवल बिक्री प्राप्ति	****	****	****	****
सूचकांक	100	94.5822	108.181	114.18
बेची गई वस्तु की लागत	****	****	****	****
सूचकांक	100	95.916	98.1771	110.31
सीओजीएस/बिक्री अनुपात	****	****	****	****
सूचकांक	100	101.416	95.9396	94.43

44. जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के घरेलू समान उत्पादों का कोई कीमत अवमूल्यन प्रतीत नहीं होता है।

ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों से संबंधित परिणामी प्रभाव - घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी कारकों एवं संकेतकों का विश्लेषण

माँग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा				
	2000-01	2001-02	2002-03	जन.- दिस.'03
घरेलू उद्योग की बिक्री	166695	176644	184977	165343
अन्य बिक्री	59687	75274	110313	109216
आयात-ज्ञात	31,095	18,384	3,460	28,808
कुल बाजार	257477	270302	298750	303367
बाजार हिस्से में परिवर्तन				
कुल बाजार	257477	270302	298750	303367
कुल बाजार में परिवर्तन		4.98	16.03	17.82
घरेलू उद्योग का उत्पादन	166705	177624	189908	168363
घरेलू उत्पादन में परिवर्तन		6.55	13.92	0.99
पाटित आयात	31,095	18,384	3,460	27,312
पाटित आयात में परिवर्तन		-40.88	-88.87	-12.17
अन्य आयात	-	-	-	1,496
अन्य आयात में परिवर्तन				
% हिस्सा				
घरेलू उद्योग	64.7	65.4	61.9	54.5
अन्य उत्पादक	23.2	27.8	36.9	36.0
पाटित आयात	12.1	6.8	1.2	9.5
अन्य आयात	0	0	0	0.5

घरेलू उद्योग पर प्रभाव - बाजार हिस्से से संबंधित आंकड़े				
	2000-01	2001-02	2002-03	जन.-दिसं.03
घरेलू खपत की मात्रा	257477	270302	298750	303367
घरेलू उद्योग हिस्सा	64.7	65.4	61.9	54.5
संचित आयात हिस्सा	12.1	6.8	1.2	9.0
अन्य उद्योगों का हिस्सा	23.2	27.7	36.9	36.0
कुल आयातों का हिस्सा	12.1	6.8	1.2	9.5
कुल %	100	100	100	100
घरेलू खपत का मूल्य				
पाटित आयात	3328.00	2009.00	380.00	4085.00
अपाटित आयात	0.00	0.00	0.00	195.00
भारतीय उद्योग बिक्री	44307.49	46743.38	58866.06	62261.74
राशि	47635.49	48752.38	59246.06	66541.74
भारतीय उद्योग का हिस्सा	93.01	95.88	99.36	93.57
संचित पाटित आयात का हिस्सा	6.99	4.12	0.64	6.14
अन्य आयातों का हिस्सा	0.00	0.00	0.00	0.29
कुल आयातों का हिस्सा	6.99	4.12	0.64	6.43
कुल %	100	100	100	100

देश में समान उत्पादों की मांग में समीक्षा अवधि के दौरान (जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में) 17% की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के हिस्से में 10% की कमी आई है, तथापि, सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के हिस्से में भी कमी आयी है। विशेषतः अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा कुल मांग में उतनी ही मात्रा में बढ़ गया है। वास्तव में, समीक्षा अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन के हिस्से में थोड़ी वृद्धि हुई है।

बिक्री मात्राएं एवं माल सूचियां

माल सूचियों पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव				
	2000-01	2001-02	2002-03	जन.-दिसं.03
माल सूची/स्टॉक	17507	15530	15208	10468
बिक्री मात्रा मी.टन	166695	176644	184977	165343
बिक्री की मात्रा में माल का %	10.50	8.79	8.22	6.33
सूचीकृत स्टॉक	100.00	83.71	78.28	60.28

46. जैसा कि ऊपर दिखाई देता है समान उत्पादों की बिक्री मात्रा में आधार वर्ष से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि वस्तु सूची बिक्री मात्रा की तुलना में समीक्षा के दौरान कम हुई है। समीक्षा अवधि के दौरान अन्तिम स्टॉक में कमी आई है।

उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग

47. घरेलू उद्योग की क्षमता इन सम्बद्ध वस्तुओं के लिए विशिष्ट नहीं है और सम्बद्ध वस्तुओं के लिए विशिष्ट नहीं है और सम्बद्ध वस्तुओं के साथ संयंत्र आटोमोबाइल एवं गढ़ाई इकाइयों में प्रयोग होने वाली अन्य वस्तुओं का विनिर्माण भी करता है तथा इन वस्तुओं की घरेलू बाजार में बिक्री की जाती है। प्राधिकारी ने संयंत्र का क्षमता उपयोग समग्र रूप से और सम्बद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता उपयोग पृथक रूप से भी निकाला है।

समग्र रूप में संयंत्र

समग्र रूप में संयंत्र की उत्पादन क्षमता एवं उपयोग					
		एम01	एम02	एम03	जांचावधि
क्षमता		293450	293450	293450	293450
संयंत्र क्षमता उपयोग	%	77.08336	87.39506	99.39719	104.6081
कल्याणी		****	****	****	****
आईएसएसएएल		****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113.3773	128.9477	135.7078

उत्पादन क्षमता एवं उपयोग (सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन ध्यान में रखते हुए)				
	2000-01	2001-02	2002-03	जनवरी-दिसंबर, 03
क्षमता	293450	293450	293450	293450
सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन (घरेलू उद्योग)	166705	177624	189908	168363
सम्बद्ध वस्तु के लिए क्षमता उपयोग का %	56.81	60.53	64.72	57.37

48. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, समीक्षा अवधि के दौरान कुछ क्षमता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में जांचावधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई है और इसलिए आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, संयंत्र उपयोग को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि क्षमता उपयोग 100% से अधिक है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि सम्बद्ध वस्तुओं के साथ संयंत्र ने आटोमोबाइल अथवा गढ़ाई इकाइयों में प्रयोग के लिए अन्य वस्तुओं का भी विनिर्माण किया है और ये वस्तुएं घरेलू बाजार में लाभ के साथ बेची जा रही हैं, यद्यपि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनकी लाभप्रदता अभी भी बेहतर रही होती यदि उन्होंने सम्बद्ध वस्तुओं का विनिर्माण कर उनकी बिक्री घरेलू बाजार में की होती।

लाभ एवं उत्पादन

लाभों में वास्तविक एवं संभावित कमी				
	2000-01	2001-02	2002-03	जन.- दिस. '03
बिक्री मूल्य लाखों में घरेलू उद्योग	****	****	****	****
सूचकांक	100	100.227	113.541	115.88
बिक्री मात्रा घरेलू उद्योग (मी. ट.)	****	****	****	****
सूचकांक	100	105.968	110.967	99.19
बिक्री मूल्य रु. प्रति यूनिट	****	****	****	****
सूचकांक	100	94.5822	102.32	116.83
उत्पादन लागत रु. मी. टन	**	****	****	****
सूचकांक	100	95.916	98.1771	110.31
लाभ/हानि प्रति यूनिट	-****	-****	-****	****
सूचकांक	-100	-118.55	27.8733	0.27
बिक्री पर लाभ (लाख रु.)	-****	-****	-****	****
सूचकांक	-100	-125	-30.9	0.27

49. समीक्षा अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है । तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है ।

रोजगार, मजदूरियाँ एवं उत्पादकता

रोजगार एवं मजदूरी पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
कर्मचारियों की संख्या	****	****	****	****
% परिवर्तन		4.77	-0.42	-2.13
बिक्री/रोजगार की मात्रा	****	****	****	****
सूचकांक	100.00	101.15	106.37	97.14

वेतन एवं मजदूरी

		ए एम01	एएम02	एएम03	जांचावधि
वेतन एवं मजदूरी	रु. प्रति मी. टन	****	****	****	****
कल्याणी		****	****	****	****
आईएसएसएएल		****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100.0	112.8	120.1	122.2

उत्पादकता				
	2000-01	2001-02	2002-03	जन.- दिस. 03
कुल कारोबार लाखों में- घरेलू उद्योग	****	****	****	****
सूचकांक	100	101.21	114.34	116.94
कर्मचारी	****	****	****	****
सूचकांक	100	105	104	102
उत्पादकता % कुल कारोबार के आधार पर	****	****	****	****
सूचकांक	100	96.6	109.6	114.5

50. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है समीक्षा अवधि के दौरान उत्पादकता में वृद्धि हुई है। समीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है यद्यपि उसी अवधि में कर्मचारी को बिक्रियों की मात्रा के औसत में मामूली कमी आई है। समीक्षा अवधि के दौरान वेतन एवं मंजदूरी में तदनुरूपी वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

पूंजी जुटाने की क्षमता, निवेश पर आय एवं अन्य वित्तीय संकेतक

			एएम01	एएम02	एएम03	जांचावधि
लाभ/हानि प्रति मी. टन	रु./मी. टन		(****)	(****)	(****)	****
कल्याणी			(****)	(****)	****	****
आईएसएसएएल			(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	सूचकांक		100	119	28	0 (मामूली लाभ)
कुल लाभ/हानि	रु. लाख		(****)	(****)	(****)	****
कल्याणी			(****)	(****)	****	****
आईएसएसएएल			(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	सूचकांक		100	126	31	0 (मामूली लाभ)

			एएम01	एएम02	एएम03	जांचावधि
लगाई गई पूंजी पर आय एनएफए			****	****	****	****
कल्याणी			****	****	****	****
आईएसएसएएल			****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक		100.00	46	98	114

			एएम01	एएम02	एएम03	जांचावधि
नकद लाभ	रु. लाख		****	****	****	****
कल्याणी			****	*	****	****
आईएसएसएएल			****	*	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक		(100.0)	(140.1)	87.3	143.5

51. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, जांच अवधि के दौरान कम्पनी की लाभप्रदता में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग ने समीक्षावधि के शुरुआती वर्षों के दौरान रहे घाटों की तुलना में जांच अवधि के दौरान थोड़ा लाभ प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग का नकद लाभ सकारात्मक है और पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। समीक्षावधि के दौरान, जांच अवधि के दौरान लगायी गयी पूंजी पर आय में वृद्धि हुई है और यह प्रवृत्ति समीक्षा जांच के दौरान जारी रही है।

कीमत एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

52. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों की कीमत कटौती, कीमत मंदन तथा कीमत न्यूनीकरण से संबंधित पैरों में पहले ही विस्तार से जांच की गई है। घरेलू बाजार के विभिन्न वृद्धि मापदण्डों पर वास्तविक तथा संभाव्य प्रभावों की विभिन्न क्षति संबंधी मापदण्डों की प्रवृत्तियों से संबंधित पूर्ववर्ती पैराग्राफों में व्याख्या की गई है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

53. भारत में संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तुओं के पाटन मार्जिन का पूर्ववर्ती पैराग्राफों में निर्धारण किया गया है और इसे पर्याप्त समझा गया है।

पूंजी जुटाने की योग्यता

54. घरेलू उद्योग के रिकॉर्ड की जांच करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की योग्यता पर प्रभाव पड़ेगा।

घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधी निष्कर्ष

55. पाटनरोधी उपाय लागू करने के पश्चात घरेलू उद्योग की स्थिति स्थिर हो गई है। वर्ष 2000-01 और जांच अवधि के बीच संबद्ध देशों से पाटित आयातों में मात्रा में बढ़ोतरी नहीं हुई और वास्तव में मात्रा में 10% से भी अधिक की गिरावट आयी और मांग के अनुपात में उनमें क्षति अवधि के दौरान 20% की गिरावट आयी। जहां तक निर्यात कीमतों का संबंध है, वे समूची विचाराधीन अवधि के दौरान वास्तविक रूप से बढ़ी और संबद्ध देशों से इन आयातों के कारण कीमत कटौती मार्जिन महत्वहीन था। यह भी नोट किया जाता है कि पाटित आयातों

से कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती नहीं हुई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग की कीमतें कम नहीं हुई और वास्तव में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कोई कीमत मंदी प्रकट नहीं हुई थी। यह सभी कीमत वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग को सामान्य लाभ के लिहाज से घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार के साथ हुआ। पाटित आयातों का कीमतें (पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर) समूची विचाराधीन अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों के बराबर थीं और इससे उन पर कोई दबाव नहीं पड़ा जिससे घरेलू उद्योग को कीमतों में उत्पादन लागत में वृद्धि से अधिक वृद्धि करने में सहायता मिली। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान क्षमता में परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन संयंत्र उपयोग अथवा संयंत्र द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं के क्षमता उपयोग में 35% की वृद्धि हुई है। यद्यपि उत्पादन और बिक्री मात्रा में क्षति अवधि के दौरान अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसी अवधि के दौरान माल सूचियों या स्टॉक में अत्यधिक गिरावट आयी है और बिक्रियों के अनुपात में मालसूची में अत्यधिक गिरावट आयी है। यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान गिरावट आयी है, यह हिस्सा अन्य उत्पादकों द्वारा ले लिया गया है जिन्होंने इस जांच में भाग नहीं लिया है। घरेलू उद्योग वर्ष 2000-01 के दौरान अत्यधिक घाटे की स्थिति से पुनः लाभ की स्थिति में आ गया है। घरेलू उद्योग के कारोबार में वृद्धि हुई है और इसी अवधि के दौरान उत्पादकता में भी 15% की वृद्धि हुई है। लगाई गई पूंजी पर आय में भी इस अवधि के दौरान 14% की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी के नकद लाभ में सुधार हुआ है और यह पूर्ववर्ती वर्ष सड़ 50% बढ़ गया है। इसलिए क्षति के संकेतक इस संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग को क्षति प्रदर्शित नहीं करते हैं। यद्यपि क्षति मानदंड जैसे घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी, उत्पादन और पूंजी पर अपर्याप्त आय नकारात्मक रुख दर्शाते हैं, पाटित आयातों से हुई क्षति के जारी रहने संबंधी स्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकती थी।

छ. पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा आवृत्ति होने की संभावना

घरेलू उद्योग के अनुरोध

56. घरेलू उद्योग ने पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा आवृत्ति होने की संभावना के संबंध में विभिन्न दलीलें प्रस्तुत की हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि वर्तमान जांच समीक्षा जांच है इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की समीक्षा के अधीन अपेक्षाओं के संदर्भ में जांच की जानी अपेक्षित है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में पहले ही पर्याप्त सीमा तक कटौती कर रहे हैं। यदि वर्तमान शुल्क

को हटाया जाता है तो कीमत कटौती की सीमा में आगे वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक है। इसलिए शुल्क को हटाए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में परिणामी गिरावट के साथ विदेशी उत्पादकों के बाजार हिस्से में आगे वृद्धि होगी। निर्यातकों की बाजार दशाओं तथा परिस्थितियों के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि ओईएम के (निर्यातक) का विश्लेषण यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कंपनी अत्यंत कठिनाईयों का सामना कर रही है। कंपनी के घाटे कई गुना बढ़ गए हैं। इसके साथ ही कंपनी की सकल अचल परिसंपत्तियों में भी वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से पाटन किए जाने के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय घाटे हुए हैं। अतिशेष उत्पादन क्षमता के कारण कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए हमेशा दबाव में रहती है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि शुल्क हटाए जाने से निर्यातक को भारत में अत्यधिक परिमाण के निर्यात करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। यह भी माना गया है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों ने उनकी घरेलू मांग की तुलना में अतिरिक्त क्षमता बना ली है। इस्पात के मामले में सामान्य रूप से तथा संबद्ध वस्तु के मामले में विशेष रूप से रूस विश्व के अग्रणी उत्पादकों तथा निर्यातकों में से है। ऐसी स्थिति में शुल्क के हटाए जाने से विदेशी उत्पादक को बाजार आप्लावित करने के अत्यधिक अवसर प्राप्त होंगे। आगे यह जोड़ा गया है कि जबकि मौजूदा शुल्क इन आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने में अपर्याप्त है तथा पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिनों से पर्याप्त रूप से कमतर हैं वहीं यह अनुरोध किया गया है कि उपायों को वापस लेने से देश में उत्पादों का और आयात होगा जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हो रही क्षति गहनतम हो जाएगी।

57. प्रकटीकरण विवरण को जारी करने के पश्चात, आयातक-याचिकाकर्ता ने क्षति की पुनरावृत्ति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की पुनरावृत्ति के संबंध में किसी परिणाम पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी के समक्ष दलीलों के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (vii) की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है तथा यह भी बताया है कि नियमावली में विनिर्दिष्ट कोई भी मानदण्ड इस मामले पर लागू नहीं होते।

प्राधिकारी द्वारा जांच

58. प्राधिकारी ने दोनों हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह दावा कि संबद्ध वस्तुओं के लिए संबद्ध देशों में

उत्पादन क्षमताएं संबंधित देशों में मांग की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक है, को उनके द्वारा अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। आगे यह बताया गया है कि इन देशों में भारतीय बाजार को आप्लावित करने के लिए प्रयुक्त फालतू उत्पादन क्षमताओं के पर्याप्त हिस्से का दावा किसी साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से विदेशी उत्पादकों के बाजार में आगे वृद्धि होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट दूसरे भारतीय घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि द्वारा अवशोषित कर ली गई है, न कि विदेशों से पाटित आयातों द्वारा।

59. घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, जोकि क्षति से खतरों के संबंध में हैं तथा जिसे क्षति की संभावना के मौजूदा विश्लेषण के संबंध में प्रासंगिक माना जाता है, के अनुबंध 2 के पैराग्राफ (vii) पर विचार किया है।

" वास्तविक क्षति के खतरे संबंधी कोई निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि केवल आरोप, कल्पना अथवा दूरस्थ संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें पाटन के कारण क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वानुमति तथा सन्नकट होनी चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की विद्यमानता के संबंध में कोई निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

- क) वास्तविक रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि महत्वपूर्ण दर ;
- ख) किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर ध्यान देते हुए भारतीय बाजारों में वास्तविक रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य, अथवा आसन्न वास्तविक वृद्धि;
- ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर पर्याप्त मंदनकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ता है, तथज्ञा आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी; तथा
- घ) जांच-पड़ताल की गई वस्तु की माल सूची।"

60. यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमों में चार सूत्रीय जांच का निर्धारण किया गया है। इनमें से पहला पाटित आयातों में बढ़ोतरी से संबंधित है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तथ्यों से यह पता चलता है कि पाटित आयात वास्तव में संबद्ध देशों से हुए हैं। इसके अलावा संबद्ध देशों में उत्पादन से अधिक उत्पादन क्षमता होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि समीक्षावधि के दौरान निर्यात कीमत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। माल सूची के संबंध में निर्यातक देशों में उत्पादकों के पास तैयार माल सूचियों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष

61. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि -
- (i) जांच अवधि के दौरान रूस से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात सामान्य से कम मूल्यों पर किया गया है। जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से कोई आयात नहीं किये गये हैं। अतः चीन जन.गण. के लिए मूल्य जाँच में निर्धारित पाटन मार्जिन पर इस समीक्षा जांच के दौरान विचार किया गया था।
 - (ii) तथापि, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति जारी रहने की स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी है।
 - (iii) यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।

ज. सिफारिश

62. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को किसी वास्तविक क्षति की पुष्टि नहीं हुई है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है, प्राधिकारी संबद्ध देशों के खिलाफ शुल्क जारी रखने के बारे में कोई औचित्य नहीं पाते हैं और उपर्युक्त नियमावली के नियम 23 के अनुसार संबद्ध देशों अर्थात् चीन जन. गण. तथा रूस के विरुद्ध लागू पाटनरोधी

शुल्क के निरसन की सिफारिश करते हैं। अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी दिनांक 25.6.2001 की अधिसूचना संख्या 65/2001-कस्टम के तहत लगाए गए प्लाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करते हैं जो केंद्र सरकार के अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

63. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकार अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज़, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Final Findings

New Delhi, the 20th May, 2005

Subject : Mid-term Anti-dumping Review investigations in the matter relating to imports of certain types/ grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds having 70 mm to 250 mm diameter from Russia and China PR.

No. 15/6/2004-DGAD.—A. Background of the Case

1. The Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 issued public notice vide Notification No. 31/1/99-DGAD dated 9th December, 1999 for initiation of anti dumping investigation concerning certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds originating in or exported from Russia, China and Ukraine. The Designated Authority recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of certain grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Russia and China PR (hereinafter referred to as subject countries) falling under sub-headings 7206.90, 7207.19 and 7207.20 and the findings were published vide Notification no. 31/1/99 dated 1st December, 2000. The Designated Authority came out with final findings on 1st June, 2001 and definitive anti dumping duty was imposed by Customs on 25th June, 2001.

2. Following the submission of a request by M/s Maharashtra Seamless Ltd which contained positive evidence necessitating the need for a mid term review, the Authority issued a public notice dated 24th May 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary,

initiating Anti-Dumping mid term review investigation under Rule 23 of the Antidumping Rules read with Article 11.2 of the Agreement on Antidumping, in respect of the duty in force against the subject countries as above, to determine whether the continued imposition of the duty is required to offset dumping, and whether injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

B. Procedure Adopted

3. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:
 - (i) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, along with the initiation notification, to all known exporters/producers in the subject countries, and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information;
 - (ii) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the review investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
 - (iii) Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).
 - iv) Investigation was carried out for the period starting from 01.01.2003 to 31.12.2003 (POI). However, injury examination was conducted for a period from AM 2001, AM 2002, AM 2003 and POI.
 - (v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;
 - (vi) No response to the initiation notification was received from any other exporter, importer and associations except M/s Kunal corporation, Mumbai and M/s Federation of Indian industries (FII), Steel re-rolling Mills Association of India and the applicant for this review.
 - (vii) M/s Indian Seamless steel and alloys Ltd, Pune and M/s Kalyani steel, Pune submitted their responses opposing the review on behalf of domestic industry.

- (viii) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.
- (ix) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- (x) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- (xi) The Authority held a public hearing on 7.12.2004 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the various interested parties. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties along with the rejoinders and other submissions have been considered by Designated Authority in this disclosure statement. In accordance with Rule 16 of The Rule supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 10th May 2005 and comments received on the same are duly considered in Final Findings.
- (xii) **** In the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'

4. The Product under consideration is "certain types/grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds having 70 mm to 250mm diameter conforming to IS specification or any other international specification equivalent to IS standards". The list of grades as mentioned in the initiation notification (of the original investigation) dated 9.12.99 and corrigendum dated 21.1.2000 remains the same. Certain arguments have been raised in the written submissions by the petitioner importer that certain types/grades of the subject goods do not find mention in the corresponding IS classifications and hence they are required to be deleted from the scope of the product. However, no detailed submissions or evidence in support of their claim have been submitted to the Authority.

Following the issuance of disclosure statement, the petitioner importer has once again reiterated the fact that not all 29 grades fall within the product scope and some of the IS specification have been deleted from BIS specification list and therefore, all 29 grades cannot be continued within the scope of product under consideration. The authority has examined the argument of the petitioner-importer and notes that their arguments are unsubstantiated and uncorroborated with any evidence. In view of the above, the Authority confirms the product under consideration and like article as decided and held in the original investigation and also in the initiation of the review (read along with corrigendum). The product under consideration is classified under sub-head 7206.90, 7207.19 and 7207.20 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The Classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations.

D. Various issues raised by various interested parties and the examination by the Authority

D.1 Issues of standing, domestic industry and related parties - Views of the domestic industry, the petitioner and examination by the Authority

5. The petitioner for the Review M/s. Maharashtra Seamless Ltd (MSL) in their written submission followed by a rejoinder have claimed that both M/s. Kalyani Steels Limited (KSL) and M/s. Indian Seamless Steel Alloys Ltd (ISSAL) cannot be treated as domestic industry by reason of their relationship with the importer. In their argument, the petitioner has submitted that M/s. ISSAL has been a major supplier of subject goods to M/s. Indian Seamless Metal Tubes Ltd (ISMT) and with effect from 1st April 2003 both the companies have been undergoing a combined restructuring proposal which provides, inter alia, for merger of both the companies. They have claimed that under these circumstances there are grounds to believe that effect of relationship is such so as to cause both the companies to behave differently from non-related companies as required under explanation (a) to rule 2(b) and, therefore, both ISSAL and ISMT shall be treated as related to each other. Similarly, the petitioner has also stated that by virtue of the fact that M/s. KSL holds significant shares in ISMT and one of their director is common to both the companies, these two companies shall be deemed to be related to each other. In view of the above, it has been contended that both M/s. KSL and M/s. ISSAL are related to ISMT who is the importer of subject goods from the subject countries and therefore, in terms of Rule 2(b) they may be deemed not to form part of domestic industry.

6. The petitioner has further disputed the claim of the domestic industry that M/s. KSL, ISSAL and M/s. Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) account for 100% of the production of the subject goods in

India. They have claimed that in the total domestic production, other domestic producers like MUSCO and SAIL Durgapur have not been taken into account in their domestic industry. Further, they have stated that they are not related to M/s. JSPL within the meaning of antidumping rules. Thus, they have requested the authority to treat JSPL as a domestic producer who opposes the petition and thus, the authority is requested to examine the standing of KSL and ISSAL in terms of relevant antidumping rules.

7. The authority has examined the contention of the petitioner and the domestic industry. A look at the transaction wise import statistics from the secondary sources indicate that a small quantity of 412 MT of the subject goods was imported by the ISMT during the POI from the subject countries. However, this quantity is considered as insignificant as it amounts to less than 2% of the subject goods imported into India and is negligible as compared to the production of domestic industry during the POI and of the total demand of the subject goods during the POI. Accordingly, the Authority concludes that very small quantity of imports of the subject goods have been made from the subject countries during the period of investigation by ISMT and hence the arguments regarding the relationship of M/s. KSL and ISSAL with importer (ISMT) does not hold ground. Further no evidence has been placed before the Authority by the petitioner importer that there are grounds to believe that the effect of the relationship between the domestic industry and importer is such as to cause both the companies to behave differently from non related companies. In view of the above, both M/s. KSL and M/s. ISSAL are being treated as domestic industry within the meaning of antidumping rules. With regard to allegation of relationship between the JSPL and MSL, the authority concludes after examining relevant records placed before it that M/s. MSL and M/s. JSPL are not related parties within the meaning of antidumping rules and therefore, M/s. JSPL is treated as a domestic producer who has, however, not taken part in the investigation. The Authority, therefore, has examined M/s KSL and M/s ISSAL for the purpose of injury as mentioned in the Annexure III of this disclosure statement. Following the issuance of disclosure statement, the petitioner-importer has submitted that the injury has been determined based on the data pertaining to M/s. Kalyani Steel Limited and M/s. ISSAL only. They have added that details regarding selling prices of JSPL along with the Chartered Accountant Certificate has already been submitted to the authority and the prices submitted by them should be considered for the purpose of determining price undercutting and price depressions etc. The authority has examined the contention of the petitioner-importer and again notes that adequate opportunity was extended to M/s. JSPL to submit the information pertaining to their selling prices and cost of production as per the domestic industry proforma. However, they have chosen not to participate in the subject investigation and, therefore, the authority has

examined M/s. KSL and M/s. ISSAL for the purpose of injury as mentioned in the annexure III of the disclosure statement.

D.2 Other Issues: Initiation of review : arguments by the petitioner importer, domestic industry and examination by the Authority

8. The domestic industry has argued that under Article 11.2 of ADA read with Rule 23 of Indian Antidumping Rules, substantiation of grounds of review are mandatory and the applicant has failed to do so. Therefore, the initiation of the review is flawed. The applicant importer has argued that the Indian Law requires the Authority to review the need for continuation of duty from time to time and does not cast an obligation on the party seeking a review to provide substantial evidence. However, they had provided positive information, as required under Article 11.2 of ADA, on several grounds and sufficient information was available with the Authority to initiate a review. The domestic industry has further claimed that onus of establishing need for withdrawal is on petitioner, as the review investigations are being undertaken to examine the need for continued imposition. Since the petitioner has failed to establish the need for withdrawal, the anti dumping duties in force must be continued.

9. The Authority has carefully examined various submissions made by the interested parties in connection with the initiation of this review investigation.

10. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately. The Authority has examined these arguments and is of the view that what is required for initiating a review is positive information with the Authority on which the Authority can rely upon to decide whether a review is required to examine the need for continued imposition of the duty. In the instant case the applicant had filed sufficient positive information before the Authority in its review application and the review was initiated based on the positive information filed. Production of evidence to substantiate the claims and counter claims by various

parties are the matter of investigation and are to be submitted by the parties including the party making a request for review during the course of investigation. The outcome of the review will however, depend upon the quality of evidence submitted by various parties to the review.

D. 3 Other issues: issues raised by Steel re-rolling Mills Association of India and other importers

11. The Steel re-rolling mills Association of India has submitted that billets is the main raw material for the steel re-rolling mills across the country which cater to 58% of the finished steel demand in the country and large number of downstream industries rest on the production of steel re-rollers. They have requested for increased availability of billets for steel re-rollers and downstream industries. They have also stated that antidumping duties on all types of steel and from all countries should be removed immediately as the dumping duties were levied at the time of glut in the world steel prices to protect the local steel industries.

Examination by the Authority

12. The authority has examined the claim in its analysis in the para relating to conclusions on injury in these findings.

E. DUMPING DETERMINATION

13. Under Section 9A (1) I of the Customs Tariff Act 1975, Normal value in relation to an article means:

The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

14. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). None of the exporters have responded to the initiation and questionnaire in any form and consequently, they have been treated as uncooperative in this investigation.

15. None of the known exporters has responded to the exporters' questionnaire by giving information with regard to various appendices mentioned in the exporters' questionnaire.

(a) Normal Value & Export Price:

16. The Authority notes that the none of the exporters from subject countries have submitted any information as required under the exporter's questionnaire. It is also noted that they have also not supplied any information rebutting the presumptions as mentioned in the 8(3) of the Annexure I of the Anti Dumping Rules pertaining to Non market economy. As no information has been submitted under various Appendixes, the Authority cannot determine whether the domestic sales have made in the ordinary course of trade. In the absence of relevant information from the exporter, the Authority has constructed the normal value as per para 7 of the Annexure 1 of the AD Rules for all producers/exporters from China PR and Russia. Export price at the ex. factory level has been determined by taking weighted average export price to India after taking account total volume of imports from Russia with applicable adjustments. As no export price is available in case of imports from China PR, no dumping margin is proposed to be determined in this review. After the issuance of disclosure statement, the importer-petitioner has requested the designated authority to disclose the components of normal value and the basis on which these components were arrived at. The authority has examined the contention of the petitioner-importer and notes that the constructed normal value arrived at for the purpose of determining the normal value, has been constructed as per para 7 of the annexure 1 of the antidumping rules for all producers/exporters from China PR and Russia and while constructing the normal value, the cost of production in India, duly adjusted including the selling general and administrative overheads along with reasonable profit has been taken into account. As some information pertain to the cost of

production of the domestic industry, the details pertaining to the normal value has not been disclosed.

(b) Comparison

17. For the purpose of a fair comparison between the normal value and export price at an ex factory level, due allowance in the form of adjustments was made for differences which affect prices and price comparability.

(c) Dumping Margin:

18. In accordance with Rule 6(iv) of annexure I to the anti dumping rules, the dumping margin was established on the basis of weighted average normal values with the weighted average export price. The comparison showed the existence of dumping of the subject goods by the exporter from Russia during the POI. The weighted average dumping margin, expressed, as a percentage to the export price has been determined and is 36.56% from Russia. As no exports have taken place from China PR during the POI, no new dumping margin is determined during the review investigations and dumping margin as determined during the original investigations (105%) have been considered in this review investigations.

	Normal Value US\$/ MT	Export Price US\$/ MT	Dumping Margin US\$/ MT	Dumping Margin %
Russia	****	*****	****	36.56

F. INJURY DETERMINATION

F.1 Cumulative Assessment of Injury

19. The Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules requires that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that

- I) the imports from individual countries are either above de minimis or cumulatively account for more than 7% of imports;
- II) the dumping margin against individual countries are above 2%; and
- III) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles

20. In this connection the Authority has verified the import statistics from the subject countries and has found that there are no imports from China PR during the POI and also three years prior to that. As no imports from China PR have come into this country, the Authority has examined the impact of dumped imports from Russia only with regard to various parameters as illustrated in the article 3.4 of the ADA and in terms of rule 11 of the Anti dumping rules.

F.2 Continuation of Injury

F.2.1 Views of the interested parties and Examination by the Authority

21. The domestic industry has argued that exporters from Russia continued dumping of material in the Indian market. Increase in export price is a reflection of the increase in the cost of production. However, even full increase in the cost of production has not been adequately taken care of by the exporters and dumping margin has in fact increased. It has been further argued that exporters from China have not been able to export the material due to imposition of anti dumping duty. Dumping would commence once again the moment the duties are removed. In other words, injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duty. It has been further argued that domestic industry is suffering continued injury, even though the same has improved. Further, should the anti dumping duties in force be revoked, the injury to the domestic industry would intensify. The domestic industry has submitted that landed price of imports from subject countries is significantly lower than selling price of the domestic industry causing severe price undercutting in the Indian market.

22. With regard to the production, sales and capacity utilization of domestic industry, it has been contended by the domestic industry that production, sales and capacity utilization of domestic industry has increased. It has been added that increase in production, capacity utilization and sales is the result of anti dumping duty imposed earlier, which prevented the decline in sales volume of domestic industry and helped the domestic industry improve its sales volumes. However, should the anti dumping duty be withdrawn, the sale volumes and consequently production & capacity utilization are likely to suffer, as the imports would become significantly cheaper with the revocation of anti dumping duty. With regards to productivity of the domestic industry, it has improved as a result of imposition of anti dumping duty and increase in production. Should the present anti dumping duties be revoked, the productivity of the domestic industry is likely to deteriorate.

23. With regard to the Profit/Loss, cash flow and return on capital employed, the domestic industry contends that imposition of anti

dumping duty has helped the domestic industry improve its performance in terms of these parameters. However, since the anti dumping duty imposed on OEMK was not sufficient to remove injury to the domestic industry, the domestic industry has not been able to post profits, leave aside reasonable profits.

24. It has been submitted by the domestic industry that the cost of production as also selling price of the domestic industry increased during the period under consideration. Though the industry was not earning reasonable profits, profitability did improve over the period. However, in case the existing duties are revoked, it is natural that the imports would become cheaper. Under the circumstances, given price sensitivity of the product, it is obvious that the domestic industry must either reduce its prices (which imply deterioration in profits, cash flow and return on investments) or face loss of sales. In either situation, the domestic industry is likely to suffer material injury. Further, given the level of market share enjoyed by the dumped imports, it is likely that the market share of the domestic industry would reduce should the present anti dumping duties be withdrawn.

25. It has been further submitted that landed price of imported material from Russia and Ukraine is below the selling price of the domestic industry causing price undercutting in the Indian market. Though the CIF price has increased, the selling price and cost of production of the domestic industry also increased. The domestic industry has submitted that the present investigations are review investigations and injury to the domestic industry is required to be examined in the context of the requirements under review. In this regard, domestic industry submits that the imports are already undercutting the prices of the domestic industry to a significant extent. Should the present duties be revoked, the extent of price undercutting would further increase, which would most likely result in further increased import. Amongst other factors, the domestic industry has cited factors as Vulnerability of the domestic industry, Significant price undercutting by imports with current measures, Ample production capacity of exporters, significant market share of imports, market conditions and circumstances of exporters, Export orientation of foreign producers, Price attractiveness of Indian market.

26. With regards to the volume and value of imports not sold at dumping prices, It has been added that there are no imports other than dumped imports, i.e., volume and value of undumped imports are within de-minimis limits. Further, the demand of the product under consideration has registered a positive growth. With regard to changes in the patterns of consumption, it has been added that the pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry and Technology for production of the product has not undergone any

change. With regard to the Productivity, as measured in terms of production per manpower, it has increased. Thus, the domestic industry has submitted that anti duties should not be revoked in the review investigation.

27. The petitioner M/s Maharashtra Seamless Ltd (MSL) and other interested parties in their various submissions have claimed that performance of the domestic industry has improved and the domestic industry does not suffer material injury. For the sake of brevity various arguments raised by the interested parties in their various written submissions have not been repeated in this finding. They have contended that imports have come down from 39830 MT in 2000 to 27857 MT during 2003. During the same period, CIF prices have gone up from Rs.10390 PMT to Rs.14702 PMT. In the year 2004, import quantity went up to 41802 PMT and the prices increased to Rs.19634 PMT. While the quantity increased by about 5% in the past 5 years, the prices have increased by over 89%. Further, even while prices were increasing by leaps and bounds, the volume of imports went up and did not go down. This is clear indication that the prices do not act on volumes. The impact of prices on volumes is very marginal if not altogether nil. While examining the impact of import prices on import volumes, one should also look at the prices prevailing in India. MSL has submitted data showing clearly that in each of the months from July 2003 to April 2004, the import prices were higher than the average selling of the Indian domestic industry. This also proves that import volumes increased not because of prices but because of other reasons. If volume had been a function of prices, then import volume should have come down –

- i. When import prices increased significantly; and/or
- ii. When domestic prices were lower than the import prices.
- a. Import volumes did not come down under both the situations. Further, since the domestic industry was selling at prices much below that of import prices, there is no price undercutting by the imports goods.
- b. Thus, the domestic industry cannot claim that imported goods caused injury to them. In the absence of price undercutting, causal link will be conspicuously absent.

28. During the year 1999-2000, MSL met 70% its requirement through imports and 30% through purchase from the Indian domestic industry. Year after year, the situation changed and in the year 2002-03, imports constituted only 6% as MSL was purchasing over 94% of its requirements from the Indian domestic industry. Yet, there was some increase in imports. This is mainly because of the inability of the Indian domestic industry to supply the required quantities to MSL. The Indian domestic industry has not been meeting their delivery

commitments of late. One of the reasons could be that Indian domestic industry is now concentrating more on value added products rather than on the product concerned which is semi-finished steel. The domestic industry has every right to have their own product priority but when their priority clashes with the requirement of its users, the users have to look out for other sources of supply. This is precisely the reasons as to why the imports are on the rise in spite of the fact that they are costlier than the goods supplied by the domestic industry. Thus, the increase in imports is caused by a demand-supply gap and not by reasons of price – be it import price or price of indigenous goods.

29. At the time of original investigation, the steel industry was at its lowest ebb throughout the world. Globally, steel prices had hit the bottom and the steel companies were reeling under tremendous pressure. In the past 5 years, the situation has undergone a sea change. Steel prices have recovered much more than what was expected. Steel industry is earning significantly higher profits.

30. A look at the balance sheet of JSPL and Kalyani Steel shows the profit after tax reported by the two domestic industry units in their annual accounts. The profits have gone up by 35% and 51% in the year 2002-03 for Jindal and Kalyani respectively. Again, the profits more than doubled in the year 2003-04 as compared to 2002-03 for both the companies. Such huge profits indicate that the domestic industry is in a very good shape.

31. The importer has enclosed email correspondence with Kalyani indicating that their refusal to supply the quantities asked for and committed by them. Kalyani has not been making supplies in spite of firm commitments made by them. When supply is not forthcoming from Kalyani in required quantities, MSL is left with no option but to import the subject goods, that too by paying excessive prices. It has also been submitted that landed values of imports made by MSL have been consistently higher than the price at which they procured the material from the domestic industry. This is a classic case of 'reversal causal link', i.e. an Indian user is forced to import the goods at much higher prices compared to the price at which the domestic industry is selling the goods for the reason that domestic industry does not supply the goods in required quantities.

F 2.2 Examination by the Authority

32. Indian Rules as also WTO Agreement provides standards to conduct review investigations. Basic purpose of mid term review provision is that anti dumping duties should be withdrawn if there is no

justification for continued imposition of anti dumping duty. Article 11.1 to 11.3 of ADA states as under in this regard:

- 11.1 An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury.
- 11.2 The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has lapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.
33. With regard to conducting review investigation, the Rules states as under:
- (1) The Designated Authority shall, from time to time, review the need for the continued imposition of the anti-dumping duty and shall, if it is satisfied on the basis of the information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty recommended to the Central Government for its withdrawal.
- (2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.
- (3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

34. It is evident from the above that the anti dumping duty imposed shall be withdrawn in case it is found that there is no justification for the continued imposition of such duty. Further, injury to the domestic industry, in a review, has to be examined, "mutatis mutandis", in accordance with the Rule 11. The Designated Authority is required to therefore examine whether there is justification for continued imposition of anti dumping duty, i.e., whether there is no injury to the domestic industry any longer and withdrawal of anti dumping duty is likely to result in continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

35. The Authority has taken note of various arguments raised by various parties in their submissions and issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority. The Authority notes that since a review has been initiated in terms of Rule 23 of the Antidumping Rules which requires the Authority to examine the need for continuation of the duty from time to time, the Authority has conducted this review to examine the degree and extent of dumping and injury and the need for continuation of the duty in view of various arguments raised by various interested parties during the investigation regarding the dumping and injury aspects of the case.

36. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the authorities are required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

37. For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

38. Since positive dumping margin has been established for the exports from the subject countries, entire exports from those countries has been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal links examination. Further, it has been represented before the Authority that imported subject goods are Non alloy steel billets, rounds and bars and they are competing with the Non alloy billets, rounds and bars manufactured and sold by the domestic industry in the domestic market. It is further noted that prices of the subject goods in the domestic market vary a great deal and the prices of the Non alloy grades of the subject goods are considerably less than the prices of the alloy grades of the subject goods. Therefore, for determining the price undercutting margin, the Authority has compared the landed value of the subject goods (all of which are of Non alloy grade) from subject countries with the net sales price for the domestic industry (Non alloy grade). However, for all other price effects of the domestic

industry, the cost of the production and net sales realization of the domestic like product (consisting of all the grades) have been taken into account. Subsequent to the issue of disclosure statement, the petitioner-importer has submitted that all the price effects of domestic industry should be compared by non-alloy import prices. They have further requested the authority to determine injury by evaluating cost of production and net sales realization of alloy and non-alloy products separately. The domestic industry in reply to the disclosure statement has requested the authority to examine the price effect on the monthly basis as against weighted average basis as determined by the authority. The authority has examined the contention of both the interested parties and notes that for the price undercutting margin, it has examined the domestic import prices (all of which are non-alloy) with the selling prices of the non-alloy subject goods of the domestic industry for the period of investigation. It is also noted that the data pertaining to the earlier periods were not separately available and hence the authority has evaluated the other price effects on the domestic like product as a whole.

VOLUME EFFECT and PRICE EFFECT: Volume of the dumped imports and the effect of dumped imports on prices in the domestic market for like products.

Import Volumes and share of subject countries and total demand

39. The domestic industry as well as petitioner (importer) had requested that segregation of subject goods is difficult from the DGCI&S transaction-wise data because of the fact that DGCI&S data does not reflect complete description of the product and this product is not exclusively classified in 6 or 8 digits level in the ITC HS classification. . Therefore, they have relied upon the import data published in the secondary sources like IBIS and IMPEX statistics for the relevant period.

				Quantity in MT
Domestic consumption / Demand				
	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Subject countries	31,095	18,384	3,460	27,312
Non Subject Countries	-	-	-	1,496
Total Imports	31,095	18,384	3,460	28,808
Domestic Industry	166695	176644	184977	165343

Other producers	59687	75274	110313	109216
Domestic Demand	257,477	270,302	298,750	303,367

40. From the above table, it follows that the domestic demand has increased during the POI as compared to base year by 17%. However, the share of imports from the subject countries in the total imports has declined by 5.2% during the POI as compared to the base year. Of the two subject countries, the imports from China PR have been nil during the POI as also during the three years prior to POI.

Market Share of Imports from subject countries in Total imports					
Actual data & Market share in Imports					
		2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
China (Quantity)		-	0	0	0
Market Share				0.00	0.00
Russia (Quantity)		31095	18,384	3460	27312
Market Share		100.00	100.00	100.00	94.80
	Change %		-	-	(5.20)
Total Imports(Subject Countries)		31,095	18,384	3,460	27,312
Total market share		100.00	100.00	100.00	94.80
	Change from base year		-	-	(5.20)
Other Countries		-	0	0	1497
Total Imports		31,095	18384	3460	28809
Other market share		0.00	0.00	0.00	5.20

Evolution of the Import prices

Average price of dumped imports (CIF) and domestic prices of the Domestic Industry				
	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Indexed (Import Price)	100.0	102.1	102.6	139.8
Domestic Prices (indexed)	100.0	94.8	101.9	115.9

41. From the above table, it follows that CIF prices of the dumped imports have increased by more than 39% during the POI as compared

to base year while that of domestic prices have increased by more than 15% during the same period.

Price Undercutting (PUC) from Subject and other countries	
Actual data	
	Jan-Dec'03 (Rs/MT)
Landed Price (Others)	16436.29
Selling price(Non Alloy grade)	****
PUC and PUC% from Others	**** 10-20%
Landed Price from subject countries	18883
Selling price (Non Alloy grade)	****
Price Undercutting for Non alloy steel	****
Price undercutting percentage	1-2%

42. It has been represented before the Authority that imported subject goods are Non alloy steel billets, rounds and bars and they are competing with the Non alloy billets, rounds and bars manufactured and sold by the domestic industry in the domestic market. It is further noted that prices of the subject goods in the domestic market vary a great deal and the prices of the Non alloy grades of the subject goods are considerably less than the prices of the alloy grades of the subject goods. Therefore, for determining the price undercutting margin, the Authority compared the landed value of the subject goods (all of which are of Non alloy grade) from subject countries with the net sales price for the domestic industry (Non alloy grade). The price undercutting though positive has not been considered significant (less than 2%). Here the landed value of the subject goods have been determined without taking into account the existing anti dumping duty.

Price depression

Price Depression of domestic industry from dumped imports				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Selling prices	****	****	****	****
Indexed	100.00	95	102	117

43. As seen above, there is no price depression of the domestic like products of the domestic industry on account of dumped imports from subject countries..

Price suppression

Rs/MT	AM01	AM02	AM03	POI
Landed value Dumped Imports	14591	14901	14971	18883
Index	100	102.125	102.604	129.42
Net sales realization	****	****	****	****
Index	100	94.5822	108.181	114.18
Cost of goods sold	****	****	****	****
Index	100	95.916	98.1771	110.31
COGS/Sales ratio	****	****	****	****
Index	100	101.416	95.9396	94.43

44. As seen above, there does not appear to be any price suppression of the domestic like products of the domestic industry on account of dumped imports from subject countries.

Consequent impact on these imports on domestic producers of such products- Analysis of the all factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry

Market Share of Domestic Industry in demand				
	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Domestic Industry Sales	166695	176644	184977	165343
Other sales	59687	75274	110313	109216
Imports - Known	31,095	18,384	3,460	28,808
Total Merchant Market	257477	270302	298750	303367
Changes in Mkt Share				
Total Merchant Market	257477	270302	298750	303367
Changes in Total Mkt		4.98	16.03	17.82
Domestic Industry production	166705	177624	189908	168363
Changes in Dom Prod		6.55	13.92	0.99
Dumped Import	31,095	18,384	3,460	27,312
Changes in Dump Imp		-40.88	-88.87	-12.17
Other Import	-	-	-	1,496
Changes in Other Imp				
% Share held by				
Domestic industry	64.7	65.4	61.9	54.50
Other Producer	23.2	27.8	36.9	36.00
dumped imports	12.1	6.8	1.2	9.50

Impact on domestic industry - Market Share Data				
	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Dom Consump Qty	257477	270302	298750	303367
Domestic industry Share	64.7	65.4	61.9	54.5
Cumulated Imp Share	12.1	6.8	1.2	9.0
Other Industries share	23.2	27.7	36.9	36.0
Total Imports share	12.1	6.8	1.2	9.5
Total %	100	100	100	100
Dom Consump Val				
Dumped Import	3328.00	2009.00	380.00	4085.00
Undumped Import	0.00	0.00	0.00	195.00
Indian industry sale	44307.49	46743.38	58866.06	62261.74
Amount	47635.49	48752.38	59246.06	66541.74
Indian industry Share	93.01	95.88	99.36	93.57
Cumulated Dumped Imp Share	6.99	4.12	0.64	6.14
Others Import share	0.00	0.00	0.00	0.29
Total Imports share	6.99	4.12	0.64	6.43
Total %	100	100	100	100

45. The demand of the like products in the country has increased by 17% during the period of review (in the POI as compared to the base year). The share of the domestic industry has declined by 10% over the period, however, the share of the dumped imports from the subject countries have also declined. Significantly, the share of the other Indian producers in the total demand has increased by the same amount. In fact, there has been small rise in the share of the Indian production during the review period.

Sales Volumes and inventories

Actual and Potential Negative Effects on Inventories				
	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Inventories/Stocks	17507	15530	15208	10468
Sales Volume MT	166695	176644	184977	165343
Invent % to Sales Vo	10.50	8.79	8.22	6.33
Indexed Stocks	100.00	83.71	78.28	60.28

46. As seen above, sales volume of the like products has not undergone any significant change from the base year though the

inventories as compared with the sales volume have gone down during the review. The closing stocks have declined during the period of review.

Production, capacity and Capacity utilization

47. The capacity of the domestic industry is not exclusive for this subject goods and in addition to the subject goods, the plant also manufactures other goods for use in the Automobile and in the forging units and these goods are being sold in the domestic market. The Authority has worked out capacity utilization of the plant as a whole and also the capacity utilization for the subject goods separately.

Plant as a whole

		AM01	AM02	AM03	POI
Capacity		293450	293450	293450	293450
Plant capacity Utilisation	%	77.08336	87.39506	99.39719	104.6081
Kalyani		****	****	****	****
ISSAL		****	****	****	****
Trend	Index	100	113.3773	128.9477	135.7078

Production capacity and utilization (taking into account production of the subject goods)

	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Capacity	293450	293450	293450	293450
Production of the subject goods (domestic industry)	166705	177624	189908	168363
Capacity Utilization% for the subject goods	56.81	60.53	64.72	57.37

48. As shown above, the total capacity has not undergone any change during the period of review. The production of the subject goods has gone up marginally during the POI and the capacity utilization, therefore, has increased only marginally during the POI as compared to base year. However, when taking the plant utilization into account, it is seen that the capacity utilization is over 100%. The Authority has determined that in addition to the subject goods, the plant also manufactured other goods for use in the Automobile or in the forging units and these goods are being sold profitably in the domestic market though the domestic industry has claimed that their profitability would still have been better had they manufactured and sold the subject goods in the domestic market.

Sales and Profits

Actual and Potential decline in profits				
	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Sales Value Lacs Domestic industry	****	****	****	****
Index	100	100.227	113.541	115.88
Sales quantity Domestic industry (MT)	****	****	****	****
Index	100	105.968	110.967	99.19
Selling price Rs per unit	****	****	****	****
Index	100	94.5822	102.32	116.83
Cost of production Rs. MT	****	****	****	****
Index	100	95.916	98.1771	110.31
Profit/loss Per unit	****	****	****	****
Index	-100	-118.55	27.8733	0.27
Profit (Rs lacs) on Sales	****	****	****	****
Index	-100	-125	-30.9	0.27

49. The production of the domestic industry has not changed much during the period under review as shown above. However, the profitability of the domestic industry has improved.

Employment, Wages and productivity

Actual and Potential Negative Effects on Employment and Wages				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
No of Employees	****	****	****	****

% Change		4.77	-0.42	-2.13
Volume of sales/Emp	****	****	****	****
Index	100.00	101.15	106.37	97.14

Salary and Wages

			AM01	AM02	AM03	POI
Salary & Wages	Rs Per MT		****	****	****	****
Kalyani			****	****	****	****
ISSAL			****	****	****	****
Trend	Index		100.0	112.8	120.1	122.2

Productivity

	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec'03
Turnover Lakhs - domestic industry	****	****	****	****
Index	100	101.21	114.34	116.94
Employees	****	****	****	****
Index	100	105	104	102
Productivity % in turn over basis	****	****	****	****
Index	100	96.6	109.6	114.5

50. As shown above, the productivity has increased during the period of review. The number of employees have not changed much during the period of review though the ratio of volume of sales to the employee has marginally declined during the same period. Salary and wages have shown consistent rise during the review period.

Ability to raise capital, return on investment and other financial indicators

			AM01	AM02	AM03	POI
Profit/loss per MT	Rs./MT		(****)	(****)	(****)	****
Kalyani			(****)	(****)	****	****
ISSAL			(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	Index		100	119	28	0 (marginal profit)

Total Profit/loss	Rs. Lacs		(****)	(****)	(****)	****
Kalyani			(****)	(****)	****	****
ISSAL			(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	Index		100	126	31	0(marginal profit)

			AM01	AM02	AM03	PO I
Return on Capital Employed NFA			****	****	****	****
Kalyani			****	****	****	****
ISSAL			****	****	****	****
Trend	Index		100.00	46	98	114

			AM01	AM02	AM03	POI
Cash profit	Rs. Lacs		****	****	****	****
Kalyani			****	****	****	****
ISSAL			****	****	****	****
Trend	Index		(100.0)	(140.1)	87.3	143.5

51. As shown above, the profitability of the company has improved during the POI and the domestic industry has achieved a small profit during the POI as compared to the losses it was incurring during the earlier years of the review period. The cash profit of the domestic industry is positive and has increased during the POI as compared to the preceding year. Return on capital employed has increased during the POI during the period of review and this has been consistent trend during the review investigation.

Factors effecting prices and growth

52. The factors effecting prices have already been examined in detail in the paras pertaining to the price undercutting, price depression and price suppression. The actual and potential effects on various growth parameters of the domestic industry have been explained in the earlier paragraphs pertaining to the trends of various injury parameters.

Magnitude of margin of dumping

53. The margin of dumping of the subject goods from subject countries into India is determined in the earlier paragraphs and is considered significant.

Ability to raise capital

54. After examining the records of the domestic industry, it is concluded that no adverse effect has been demonstrated which would affect the ability of the domestic industry to raise capital.

Conclusions on injury to the domestic industry

55. Following the imposition of antidumping measures, the situation of the domestic industry has stabilized. Between 2000-01 and the POI, dumped imports from the subject countries did not increase in volume and in fact reported a decline in the volume by more than 10% and as a proportion of the demand, they declined by 20% during the injury period. As regards the export prices, they increased substantially during the whole period under consideration and the undercutting margin on account of these imports from subject countries were insignificant. It is also noted that no significant price undercutting has been caused by dumped imports. Further, domestic industry prices were not depressed and in fact there is a consistent rise in the domestic selling prices of the domestic industry during the injury period. No price suppression was evident on account of dumped imports from subject countries. All this coincided with the improvement of the situation of the domestic industry in terms of price increases as well as small profit to the domestic industry. Prices of dumped imports (excluding the anti dumping duty) were similar to those of the domestic industry throughout the period under consideration and did not exert any pressure on them which helped the domestic industry to increase prices more than the rise in the cost of production. Though the capacity has not changed during the injury period, the plant utilization or capacity utilization of all goods produced by the plant has increased by 35%. Though the production and sales volume have not change much during the injury period, the inventories or stocks have gone down significantly during the same period and inventory as a proportion to sales have declined significantly. Though the market share of domestic industry has gone down during this period, this share has been taken up by the other producers who have not taken part in this investigation. The domestic industry is back into the profit from the position of significant losses during 2000-01. The turnover of the domestic industry has increased and the productivity has also increased by 15% during the same period. The return on the capital employed has increased by 14% during the same period and the cash profit relating to the subject goods of the domestic industry has improved and has grown by 50% from the preceding year. The injury indicators, therefore, do not reflect injury to the domestic industry in this subject investigation. Though injury parameters like decline in the market share of the domestic industry, production and inadequate return on the capital show a negative trend, a situation of continuation of injury caused by the dumped imports could not be established.

G. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY**Submission by domestic industry**

56. The domestic industry has submitted various arguments with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. It has been submitted by the domestic industry that since the present investigations are review investigations, injury to the domestic industry is required to be examined in the context of the requirements under review. In this regard, domestic industry submits that the imports are already undercutting the prices of the domestic industry to a significant extent. Should the present duties be revoked, the extent of price undercutting would further increase, which would most likely result in further increased import. The domestic industry has submitted that domestic industry has suffered continued material injury from the dumped imports from subject countries. There is a great possibility that revocation of duty will result in flooding of the material in the Indian market. This is evident from the continued dumping in the market. In other words, the Indian Market is vulnerable to imports, should the prices offered by the exporters be lower. Such being the case, the domestic industry is vulnerable to injury. It has also been submitted that the Petitioner is one of the major consumer of the subject goods. The sole factor for the petitioner to decide the source is the price. Such being the case, revocation of anti dumping duty would instantly result in flooding of market and loss of sales by the domestic industry. The Domestic industry maintains that the production capacity in subject countries for the product under consideration are significantly higher than demand in their respective Countries. Should the current measures be allowed to lapse, there is a threat that a significant proportion of unused production capability would be used to flood the Indian market. It has been contended that market share of imports is significant. Revocation of duty would, therefore, result in further increase in market share of Foreign Producers with consequent decline in the market share of the domestic industry. With regard to market conditions and circumstances of exporters, it has been contended that an analysis of OEMK (exporter) clearly shows that the company is facing very stiff situation. Losses to the company have increased many folds. At the same time, gross fixed assets of the company have also increased. Dumping practices have unfortunately resulted in financial losses to the company. Due to significant surplus production capacity, company always remains under pressure to sell its product. There is a great possibility that withdrawal of duty will lead to significant opportunity to the exporter to export huge quantities to India. It has also been maintained that exporters in the subject countries have built capacities far in excess of

their domestic demand. Russia is amongst leading producer and exporter in the world in respect of steel in general and the subject goods in particular. Such being the case, revocation of duty would provide a great opportunity to the Foreign Producers to flood the market. It has been further added that whilst the current duties are insufficient to remove the injury to the domestic industry from these imports and are significantly lower than the dumping margin and injury margins, it is submitted that withdrawal of measures would lead to further importation of the product in the Country, thus resulting in intensified injury to the domestic industry.

57. Subsequent to the issuance of disclosure statement, the importer-petitioner has refuted the allegations made by domestic industry with regard to recurrence of injury. They have added that the domestic industry has not submitted any evidence other than arguments before the authority to come to a finding with regard to recurrence of injury. In this regard, they have drawn the attention of the authority to para (vii) of annexure II to the antidumping rules and have added that none of the criteria specified in the rules are applicable in this case.

Examination by the Authority

58. The authority has examined the contention of both the interested parties. The authority notes that claim of the domestic industry that production capacities in the subject countries for the subject goods are significantly higher than the demand in the respective countries has still not been substantiated by them. It is further added that the claim of significant proportion of excess production capability in these countries being used to flood the Indian market, has not been substantiated with any evidence. With regard to the claim of the domestic industry that revocation of antidumping duty would result in further increase in the market of the foreign producers, the authority notes that the fall in the market share of the domestic industry has been absorbed by increase in the market share of other Indian domestic producers and not by dumped imports from abroad.

59. With regard to the recurrence of injury to the domestic industry, the Authority has taken into account paragraph (vii) of Annexure 2 to the Anti Dumping Rules which deals with threat of injury and which is considered relevant in the present analysis of likelihood of injury.

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be

clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:

- a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;*
- b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in , capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*
- c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and*
- d) Inventories of the article being investigated."*

60. It is noted that the above rule prescribes a four-point test. The first one relates to increase in the dumped imports. The facts determined by the authority show that dumped imports have actually come down from subject countries. Further, the production capacity being in excess of production in the subject countries have not been substantiated. With regards to the import prices of the subject goods from the subject countries, it is noted that export prices have increased significantly during the review period. With regard to the inventories, no evidence has been made available regarding buildup of inventories with the producers in the exporting countries. In view of the above, the claim of the domestic industry that there will be recurrence of injury is not sustained.

Conclusions

61. After considering the foregoing, the Authority concludes that -

- (i) The subject goods have been exported below their Normal Values from Russia during the period of investigation. There were no imports from China PR during the period of investigation, hence, dumping margin established during the original investigation for China PR was considered in this review investigation.
- (ii) However, a situation of continuation of injury caused by the dumped imports to the domestic industry could not be established.
- (iii) Injury is not likely to recur if the anti dumping duty imposed on the subject goods from subject countries were removed

G. Recommendations

62. Having concluded that no material injury to the domestic industry has been established on account of dumped imports of subject goods from the subject countries and there is no likelihood of recurrence of injury on account of import of subject goods from subject countries, the Authority finds no justification for continuation of the duty against subject countries and therefore, in terms of Rule 23 of the said Rules recommends revocation of anti dumping duty in force against subject countries i.e. China PR and Russia. Hence, in view of the above, the Authority recommends withdrawal of the anti dumping duty imposed vide notification, No. 65/2001-Customs dated 25.6.2001 with effect from the date of notification issued by the Central Government.

H. Further Procedures

63. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority